purposeful competition between a Government operator (DOT) and a private operator and not between two Government operators.

(d) ITI will be expected to meet the demand of the DOT and Private Service operators for equipment in competition with other manufacturers. It will also be expected diversify its products as well as customers.

अरावली पहाड़ियो में भूमि सुधार

2214. **श्री शिव प्रसाद चनपुरिया** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हरियाणा राज्य में अरावली की पहाड़ियों में कृषि उत्पादन के साथ-साथ इमारती लकड़ी ईधन की लकड़ी का विकास करने एवं चारा उगाने की दृष्टि से वहां भूमि सुधार से संबंधित एक परियोजना शुरू करने के लिए यूरोपीय समुदाय के साथ किसी करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) इस करार का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार मध्यप्रदेश में विंध्याचल और सतपुडा के पठार क्षेत्रों और पहाड़ियों में इस प्रकार की परियोजना को कार्यान्वित करने का विचार रखती है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) मार्च 1990 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसमें यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसमे यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने " अरावली की पहाड़ियां , हरियाणा में सामुदायिक भूमि का पुनरूद्धार"नामक परियोजना को अनुदान के रूप में 23.20 मिलियन इसीयू देकर वित्तपोषित करने का आश्रवासन दिया है। यह परियोजना 1990 से कार्यान्वित की जा रही है। समझौते के अनुसार , परियोजना की कुल लागत,48.15 करोड़ रूपए हैं इसको भिवानी , महेन्द्रगढ़, गुड़गांव और फरीदाबाद जिलों में सात वर्षो की अवधि में कार्यान्वित किया जाना है। इस परियोजना में अर्ध-शुष्क अरावली पहाड़ियों में पर्यावरणीय सुरक्षा और हरे आवरण की बहाली की संकल्पना की गई है ताकि स्थानीय लोगों की जीविकोपार्जन जैवमास जरूरतों को पूरा करके उनके जीवनस्तर में सुधार लाया जा सकें। स्थाई आधार पर ईधन की लकड़ी-इमारती लकड़ी घास और चारा प्रदान करने के लिए इस परियोजना के तहत 33,000 हैक्टेयर सामुदायिक भूमि को कवर किया जाएगा। इस परियोजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मिट्टी की उर्वरता बेहतर होगी। भूमि का कटाव रूकेगा और जल विज्ञान संबंधी संतुलन में सुधार होगा जिससे उस क्षेत्र में कृषि उत्पादन को लाभ पहुंचेगा।

(घ)विश्व बैंक की सहायता से 245.94 करोड़ रूपए की लागत से 1995-96 के दौरान विंध्याचल एवं सतपुड़ा के पठार और पहाड़ियों सहित समूचे मध्यप्रदेश राज्य को शामिल करने वाली एक वनिकी योजना शुरू की गई है। इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना, वनों की उत्पादकता बढ़ाना और वनों व कृषि भूमि पर वन एवं वृक्ष आवरण में वृद्धि करना है। यह परियोजना 4 वर्षो की अवधि में कार्यान्वित की जाएगी।

Industrial thefts and pilferaged In Jamshedpur

2215. DR. BAPU KALDATE: WiU the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Industrial thefts and pilferage have been reported from

Jamshedpur, the steel city as reported in the Telegraph dated 18th June, 1995; and

(b) if so, the steps taken to eradicate such inter-state organised rackets?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P.M. SAYEED): (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Running of DMU trains in Orissa

2216. SHRI BHAGABAN MAJHI: WiU the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the number of DMU trains running in different routes of Orissa as on 30th October, 1994;

(b) whether some of those DMU trains have been withdrawn from those routes;

(c) if so, the reasons therefor;

(d) whether Government propose to consider the re-introduction of DMU trains in some of those routes; and

(e) if so, the details thereof?